हमें शांति चाहिए। सिर्फ इसलिए नहीं कि यह अच्छी बात है, बल्कि इसलिए भी कि हम अगले बीस सालों तक लड़ना या लड़ाई के लिए तैयार रहना वहन नहीं कर सकते। हमें प्रतिरक्षा बजट को नियंत्रित करना होगा और सही नीतियां व नजरिया अपनाते हुए हम ऐसा कर सकते हैं। गोलियों पर खर्च का कोई प्रतिफल नहीं मिलता, लेकिन बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए खर्च हुए धन का मिलता है।

कितना महंगा झगड़ा?

चेतन भगत

लेखक भारतीय अंग्रेजी के प्रसिद्ध युवा उपन्यासकार हैं।

पिछले दिनों हमारे प्रधानमंत्री पाकिस्तानी प्रधानमंत्री से मिले और उन्होंने एक साझा बयान जारी किया। इसमें आतंकवाद को अलग रखते हुए एक-दूसरे से बातचीत करने की बात कही गई थी। इसकी व्यापक प्रतिक्रिया देखी गई। मीडिया तो रियलिटी शो से होड़ लेने के लिए सनसनीखेज न्यूज आइटम्स की खोज में रहता ही है, लिहाजा उसने इसके बारे में कई स्टोरीज चलाईं कि किस तरह हम दृढ़ता नहीं दिखा सके। कहा गया कि इस साझा बयान के जरिए हमने राष्ट्रीय अस्मिता खो दी। हमारे सांसद तो वैसे भी क्लास बंक करने वाले कॉलेज छात्रों की तरह सदन छोड़ने को उत्सुक रहते हैं और उन्होंने इस पर कई बार वॉकआउट किया।

हमारा ऐसा रवैया दर्शाता है कि हम वास्तव में पाकिस्तान के साथ निपटारा करना नहीं चाहते। हां, हम संबंध बेहतर बनाना चाहते हैं, लेकिन गहरे तक असंतोष और गुस्सा समाया है। हम पाकिस्तान को एक सबक सिखाना चाहते हैं। हम उसे उसकी हैसियत दिखाना चाहते हैं। पाकिस्तान को धिक्कारना देशभक्ति माना जाता है। इससे राजनीति भी अच्छी चलती है।

हमें लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री ने मुंबई आतंकी हमले के मसले को सुलझाने से पहले उनके साथ बातचीत के लिए राजी होकर गलती की। हालांकि हम पाकिस्तान से बात करें या नहीं, लेकिन हम असाधारण रूप से उससे जुड़े हुए हैं। हम हर तरह का संपर्क तोड़ सकते हैं, हमारे और उसके नेता एक-दूसरे को नफरत की निगाह से देख सकते हैं। फिर भी हरेक भारतीय का भविष्य पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है और हम जारी लड़ाई में अपनी ओर से हर्जाना भुगत रहे हैं। इसका कारण है हमारा प्रतिरक्षा बजट। 140,000 करोड़ रुपए (इस साल 40 फीसदी बढ़ोतरी हुई है) के साथ यह सरकार की सबसे महंगी और खर्चीली मद है, जो ज्यादातर पाकिस्तान की वजह से है।

देशभक्ति के तकाजों को देखते हुए रक्षा के खर्चों पर कभी सवाल नहीं उठाए जाते। आखिरकार *आप उन सैनिकों पर खर्च होने वाली राशि पर कैसे सवाल उठा सकते हैं जो सरहद पर अपनी जान की बाजी लगाते हैं?* फिर भी बड़ा सवाल यही है कि *अव्वल उन्हें अपनी जान देनी ही क्यों पड़ती है?* हमें समझना होगा कि हम प्रतिरक्षा पर जो धनराशि खर्च करते हैं, उसकी हमें क्या कीमत चुकानी पड़ रही है?

यह कहना अच्छा लगता है कि 'हमारी सेना मजबूत होनी चाहिए।' हालांकि हम एक गरीब मुल्क हैं। जब आप गरीब हैं तो आपको प्रैक्टिकल भी होना चाहिए। हमें अपनी प्रतिरक्षा नीति पर सर्वसम्मति तक पहुंचने से पहले इन तीन बातों पर फिर से विचार करना चाहिए।

पहली बात हमारी विदेश नीति के संदर्भ में है। हमारा विदेश नीति दस्तावेज राष्ट्रीय अहं का घोषणापत्र नहीं है। यह एक ऐसा दस्तावेज है जो यह स्पष्ट करे कि हम किस तरह बाकी दुनिया के साथ अपने संबंधों को अपने देश के फायदे के लिए बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। राजनेताओं को भूल जाएं, मैं अपने देश के साथी नागरिकों से पूछना चाहता हूं कि हम कश्मीर को किस हद तक चाहते हैं? क्या हम देश में युवा पीढ़ी के लिए कॉलेज बनाने की कीमत पर इसे चाहते हैं? क्या हम अपने किसानों के लिए सिंचाई परियोजनाओं की कीमत पर इसे चाहते हैं? क्या हम सड़कें और पावर प्लांट्स बनाने की कीमत पर इसे चाहते हैं? चाहे इसकी वजह से हमें हमेशा उच्च महंगाई के दौर में क्यों न रहना पड़े? क्योंकि भले ही प्रत्यक्ष न हो, लेकिन ये सब चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। उपरोक्त सभी मदों को इकट्ठा मिला लिया जाए, तो भी प्रतिरक्षा बजट इन सबसे ज्यादा है। हमारी सरकार के पास असीमित धन नहीं है। ऐसे में बेहतर क्या है? लड़ाई जारी रखें और विकास को रोक दें, या फिर हम शांति स्थापित करें और धन का इस्तेमाल देश को मजबूत करने में करें? विदेश नीति पत्र इसमें महती भूमिका निभा सकता है।

दूसरी बात सामरिक रक्षा गठजोड़ की है। नई वैश्वीकृत दुनिया में अर्थव्यवस्थाएं अभूतपूर्व ढंग से आपस में एक-दूसरे से जुड़ी हुई हैं। कोई भी अपने बलबूते सब कुछ नहीं करता। यदि प्रतिरक्षा का उद्देश्य हमारी सीमाओं की सुरक्षा करना है तो हम इसके लिए दूसरे देशों के साथ भी गठबंधन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अमेरिका को अपनी सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और वैश्विक आतंकवाद को खत्म करने के लिए दूसरों की काफी जरूरत है। हम उसके साथ काम कर सकते हैं- हां, उन्हें अपने देश में कुछ हद तक प्रवेश देकर। हमारे लिए इससे खुद को बचाने की लागत बच सकती है। उसके लिहाज से कहें तो अब अस्थिर इलाके पर वह कहीं बेहतर तरीके से नियंत्रण रख सकता है। हम अपने रक्षा तंत्र में अमेरिकी संबंद्धता की बात से ही सिहर सकते हैं, लेकिन स्पष्ट तौर पर देखा जाए तो यदि वे हमें हमारी सीमाओं की सुरक्षा में मदद करते हैं तो उन्हें हमारे मुकाबले क्या लाभ हासिल हो सकता है? इस तकनीक-प्रधान युग में क्या आपको वास्तव में लगता है कि अमेरिका के पास भारत के खिलाफ हमला करने की क्षमता या जरूरी जानकारी नहीं है? हालांकि वे हम पर हमला नहीं करना चाहते? उन्हें हमारे संभावनाशील बाजार से अमेरिकी उत्पादों और सस्ती आउटसोर्सिंग के जरिए बहुत कुछ हासिल करना है। खैर, हम अपनी कुछ प्रतिरक्षा उन्हें आउटसोर्स करें, उन्हें सुरक्षित महसूस कराएं और अपने लिए कुछ धन बचाएं।

तीसरी बात शांति के संदर्भ में है। लगता है बुद्ध और गांधी की यह भूमि अपने शांति के लक्ष्यों से भटक गई है। हम पाकिस्तान के साथ बात करना चाहते हैं, लेकिन हमारा ज्यादा जोर उसे नीचा दिखाने और अपनी सोच उस पर थोपने का होता है। इस तरह की हेकड़ी से सिनेमा हॉल में दर्शकों की तालियां तो बटोरी जा सकती हैं, लेकिन शांति के लिए यह रवैया ठीक नहीं है। हमें लगता है कि पाकिस्तान गलत है और कश्मीर पर हमारा हक है, लेकिन अगर हम बातचीत कर रहे हैं तो हमें दूसरी पार्टी को भी थोड़ी गुंजाइश देनी होगी। हम इस पर खुश भले ही न हों, लेकिन हम इसके साथ रहना सीख सकते हैं।

हमें शांति चाहिए। सिर्फ इसलिए नहीं कि यह अच्छी बात है, बल्कि इसलिए भी कि हम अगले बीस सालों तक लड़ना या लड़ाई के लिए तैयार रहना वहन नहीं कर सकते। हम घर के बाहर और ज्यादा सिक्युरिटी गार्ड्स की सेवाएं ले रहे हैं। ऐसा तब है जबकि हमारे पास बच्चों को स्कूल में डालने लायक पर्याप्त पैसा नहीं है। हमें प्रतिरक्षा बजट को नियंत्रित करना होगा और सही नीतियां व नजरिया अपनाते हुए हम ऐसा कर सकते हैं। गोलियों पर खर्च का कोई प्रतिफल नहीं मिलता, लेकिन बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए खर्च हुए धन का मिलता है।

और संभवतः यही बात हमारे प्रधानमंत्री के जेहन में रही होगी जब उन्होंने बातचीत जारी रखने की बात कही। कम से कम मेरे जैसा आशावादी तो यह उम्मीद कर सकता है।

chetan.bhagat@gmail.com

अपने विचारों के लिए ई-मेल करें-
letterto_editor @ mp.bhaskarnet.com

अल-शेख तो छूट गया पीछे पड़ी है शर्म

राग दरबारी | **नीरज बधवार**

जबसे गिलानी शर्म-अल-शेख से शेखचिल्ली बन लौटे हैं और डॉक्टर सिंह 'शर्म' लेकर, तमाम विपक्षी पार्टियां उनके पीछे हाथ धोकर पड़ी हैं। उनका कहना है कि ये शर्म इतनी ज्यादा है कि देश भर के नदी-नालों, कुओं-बावड़ियों का पानी भी इसे नहीं धो सकता। उन्हें आपत्ति है कि साझा बयान में बलूचिस्तान क्यों शामिल किया गया? मगर मेरा मानना है कि इस मामले में जो भी प्रधानमंत्री की आलोचना कर रहा है, वह पूरे किस्से से वाकिफ नहीं।

दरअसल पाकिस्तान की तरफ से साझा बयान में बलूचिस्तान के अलावा पंजाब, सिंध और नॉर्थ-वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में अशांति के लिए भी भारत को जिम्मेदार बताया गया था। संयुक्त बयान में आगे लिखा था कि 26/11 के हमले पर भी भारत पाकिस्तान से जवाब नहीं मांगेगा, क्योंकि उसे पता चला है कि इसके पीछे लश्कर का हाथ न हो गड़रिया का हाथ है और उस हमले में पकड़ा गया एकमात्र जिंदा शख्स कसाब न हो घनश्याम गड़रिया है।

संयुक्त बयान के मूल प्रारूप में ये सब बातें लिखी गई थीं। ड्राफ्ट देख हमारे प्रधानमंत्री पहले तो कुछ देर खामोश रहे, फिर उन्होंने गिलानी को समझाया कि अगर भारत की वजह से ही पाकिस्तान में अशांति है और हमारी वजह से ही वहां शांति आ सकती है तो तुम्हारे प्रधानमंत्री बने रहने की क्या जरूरत है? ऐसी नादानी भरी वाली बातें मत करो। दोस्ती हमेशा बराबर वालों के बीच होती है। हम आज तक कश्मीर में गड़बड़ी के लिए तुम्हें दोषी ठहराते रहे हैं। तुम भी हमें किसी एक राज्य में गड़बड़ी का दोषी ठहरा दो। मगर एक से ज्यादा तो ज्यादती होगी। ज्यादती भी क्या कहूं, हमारी छवि को देखते हुए कॉम्प्लीमेंट होगा। ऐसा करो तुम बाकी स्टेट्स निकाल दो, बस एक रहने दो।

इस एक के तौर पर बलूचिस्तान को छोड़ बाकी सबको डिलीट करवा दिया गया। भारतीय खेमे में खुशी का माहौल था। प्रधानमंत्री की इस समझदारी पर खुशी जताने के लिए हर कोई एक-दूसरे से आगे निकलना चाहता था। किसी ने बुरी नजर से बचाने के लिए उन्हें काला टीका लगाया, तो कोई फौरन उनका पसंदीदा ड्रिंक ले आया। किसी ने मौके पर फिट न होने वाला शेर पढ़ा, तो कोई अतिउत्साही मोबाइल पर ही 'सिंह इज किंग' गाना बजा नाचने लगा।

मगर मैं क्या देख रहा हूं कि जबसे वे शर्म-अल-शेख से लौटे हैं, 'अल-शेख' तो पीछे छूट गया मगर 'शर्म' उनका पीछा नहीं छोड़ रही। हर कोई उन्हें शर्मिंदा करने पर तुला हुआ है। मैं पूछता हूं कि अगर यह बयान गलत भी था, तब भी उन्हें तो प्रधानमंत्री का शुक्रगुजार होना चाहिए। यशवंत सिन्हा को तो बाकायदा थैंक्स गिविंग का एक ग्रीटिंग प्रधानमंत्री को भेजना चाहिए। कितने महीनों बाद उन्हें अपनी पार्टी के इतर किसी और के खिलाफ बोलने का मौका मिला। सालों बाद अगर वे भाजपाई दिखे हैं तो इसका क्रेडिट भी मनमोहन सिंह को जाता है। वरना तो वो कब से बीजेपी के भीतर ही विपक्षी सदस्य की भूमिका निभा रहे थे। इसी तरह अरसे से आजम-अमर के झगड़े में रैफरी की भूमिका निभा रहे मुलायम सिंह को खुद किसी से झगड़ने का मौका मिला। विदेशी नीति जैसे मामले पर सरकार को लताड़ लगा खुद को विद्वान समझने का सौभाग्य मिला। इस पर भी आप कहते हैं कि प्रधानमंत्री ने जो कहा, वह सरासर गलत था। अरे भई चुटकुले सुनाने पर पाकिस्तान में प्रतिबंध लगा है, मगर चुटकुला बनने पर भारत में तो कोई पाबंदी नहीं है।

जीवन दर्शन

आज के राजनीतिज्ञों को शास्त्रीजी का संदेश

नियमों को पद की उच्चता व निम्नता से मुक्त रखा जाना चाहिए। शास्त्रीजी के इन विचारों में स्वच्छ राजनीति की झलक मिलती है जो आज की समझौतावादी व अनैतिक राजनीति के लिए प्रेरणास्पद है।

बात उन दिनों की है जब लालबहादुर शास्त्री उत्तरप्रदेश के गृहमंत्री थे। कई लोग उनसे भेंट करने आया करते थे। शास्त्रीजी सभी से अत्यंत स्नेहपूर्वक मिलते और यथासंभव समस्याओं का समाधान करते। एक दिन वे अपने कार्यालय में बैठे कुछ आवश्यक कार्य निपटा रहे थे, तभी चपरासी ने आकर सूचना दी कि उनके कोई मित्र मिलने आए हैं। शास्त्रीजी ने मित्र को तत्काल बुला भेजा। उन्होंने मित्र के यथोचित सत्कार के पश्चात उससे आने का कारण पूछा, तो वह बोला- मेरे बेटे को थानेदार का पद इसलिए नहीं दिया जा रहा है क्योंकि तय मापदंड से उसकी ऊंचाई आधा इंच कम है। यदि आप सिफारिश कर दें तो मेरा काम बन जाएगा। शास्त्रीजी कुछ देर मौन रहे, फिर बोले- यदि तुम्हारे पुत्र का कद छोटा है तो वह थानेदार नहीं बन सकता। यह सुन मित्र रुष्ट होकर बोला- वाह शास्त्रीजी! आप भी तो बिलकुल नाटे कद के हैं तब भी प्रदेश के गृहमंत्री बन बैठे हैं और मेरा बेटा आधा इंच कम ऊंचा होने से थानेदार भी नहीं बन सकता। यह तो सरासर अन्याय है।

उसकी बात सुनकर शास्त्रीजी मुस्कराते हुए बोले- आप ठीक ही कहते हैं। मैं नाटे कद का हूं इसलिए गृहमंत्री तो बन सकता हूं किंतु थानेदार किसी सूरत में नहीं बन सकता। आपका बेटा भी छोटे कद के कारण थानेदार नहीं बन सकता। हां, किसी दिन वह गृहमंत्री अवश्य बन सकता है। मेरी शुभकामनाएं सदैव उसके साथ हैं। शास्त्रीजी के प्रत्युत्तर पर मित्र निरुत्तर हो गया। अपने जवाब से उन्होंने दर्शा दिया था कि नियम सभी के लिए समान हैं और पद के दुरुपयोग से उन्हें तोड़ने के लिए वे कतई तैयार नहीं हैं।

बात पते की

अपने समय को सर्वोत्तम ढंग से प्रयोग करने के लिए बड़ी शक्ति की जरूरत होती है।

जीने की राह

भगवान शिव समान हो शील की सुगंध

सुगंध के प्रति सबका आकर्षण होता है फिर मनुष्य जीवन तो अपने आपमें एक महक है। दुर्गंध के झोंके तो बाद में हम प्रवेश कराते हैं। गौतम बुद्ध ने कहा था कि संसार की सारी सुगंधों में श्रेष्ठ है शील की सुगंध। यह तब ही होगी जब हम शीलवान होंगे। फर्क है चरित्रवान और शीलवान होने में। शंकरजी के जीवन का एक प्रसंग है- पार्वतीजी से विवाह करने हेतु शंकरजी दूल्हा बने थे और बारात जाने के लिए तैयार थी, दृश्य विचित्र था। भूत-प्रेत तथा विचित्र शारीरिक आकृतियों के गण बाराती के रूप में थे। देवताओं की पत्नियों ने इस दृश्य को देख शंकरजी पर व्यंग्य कसा। जिसे सुनकर शिवजी पार्वती के पिता हिमालय के द्वार पर खड़े हो गए। पार्वतीजी की मां मैना ने दूल्हे को देख दुख प्रकट कर शिव का घोर अपमान किया। *जो फलु चहिअ सुरतरुहिं, सो बरबस बबूरहिं लागा।* जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए, वह जबर्दस्ती बबूल में लग रहा है यानी शंकरजी पार्वतीजी के योग्य नहीं हैं। मैना की इस उपहास भरी टिप्पणी के बाद भी दूल्हा बने शिव अपनी विनम्रता नहीं छोड़ते।

यहीं शिव के शील के दर्शन होते हैं। धैर्य व निरहंकारिता शील के आभूषण हैं। चरित्रवान और शीलवान में यही फर्क है। चरित्र हमारे द्वारा खोदे गए कुएं के जल के समान है और शील ईश्वर द्वारा उतारी गई गंगा। जब कभी आप ध्यान में गहरे उतरें, उसके बाद जो आपकी जीवनशैली होगी वही शील है। शंकरजी ने अपने दांपत्य के आरंभ के दृश्य में यह संकेत दे दिया कि बिना शीलवान बने यदि गृहस्थी में प्रवेश करोगे तो अशांति की संभावना बनाओगे।

-पं. विजयशंकर मेहता | babahanuman@hotmail.com

चरित्र हमारे द्वारा खोदे गए कुएं के जल के समान है और शील ईश्वर द्वारा उतारी गई गंगा। जब कभी आप ध्यान में गहरे उतरें, उसके बाद जो जीवनशैली आपकी होगी वही तो शील है।

संपादकीय

सू ची को सजा और भारत की चुप्पी

दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत एक तानाशाही का न सिर्फ समर्थन करता है, बल्कि खुलेआम हो रहे अन्याय के खिलाफ मुंह नहीं खोलता।

बर्मा के सैनिक शासकों ने एक बार फिर न्याय के निहितार्थ की धज्जियां उड़ाई हैं। लोकतंत्र के आंदोलन की प्रतिमूर्ति बन चुकी आंग सान सू ची को अगले 18 महीने के लिए नजरबंद कर दिया गया है। पिछले 20 सालों में चौदह वर्ष उन्होंने नजरबंदी में गुजारे हैं। नजरबंदी के दौरान एक अमेरिकी नागरिक बिना आमंत्रण के उनसे मिलने जा पहुंचा था। जॉन येटाव तैरकर उनके झील किनारे मकान में घुस गया था। इसके लिए जॉन और सू ची पर मुकदमा चला और मंगलवार को सू ची को तीन साल कैद की सजा सुनाई गई, जिसे फिर 18 महीने की नजरबंदी में तब्दील कर दिया गया मानो बर्मा के सैनिक तानाशाह उन पर मेहरबानी कर रहे हों। रंगून के तानाशाहों का उद्देश्य स्पष्ट है। अगले साल मई में वहां चुनाव होने हैं और वे नहीं चाहते कि सू ची चुनाव में भाग लें।

संयुक्त राष्ट्र संघ ने बर्मा पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए और मंगल के अमंगल के बाद उन प्रतिबंधों को और कठोरता से लागू करने का प्रण अमेरिका और यूरोप ने लिया, पर बर्मा के मोटी चमड़ी वाले शासकों पर इसका कोई प्रभाव नहीं होता। मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाई गई, लेकिन इस पर सहमति नहीं बनी क्योंकि स्थायी सदस्य चीन नहीं चाहता कि बर्मा को कोई हानि हो। चीन बर्मा के शासकों का मित्र है। बर्मा के कान पर तब तक जूं नहीं रेंगेगी, जब तक उसके पड़ोसी मित्र चीन और भारत उसके साथ हैं।

चीन तो खैर ऐसे कई आततायी सत्ता-तंत्रों का समर्थन करता है, पर दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत एक तानाशाही का न सिर्फ समर्थन करता है, बल्कि खुलेआम हो रहे अन्याय के खिलाफ मुंह नहीं खोलता। अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप और यहां तक कि बर्मा के पड़ोसी थाईलैंड, इंडोनेशिया जैसे देशों ने सू ची को सजा देने की भर्त्सना की है, पर भारत की चुप्पी नहीं टूटी।

भारत को घेरने के लिए बर्मा ने चीन को तो अपना बंदरगाह दिया है। चीन उसे उत्तर कोरिया से आणविक शक्ति दिलवा रहा है। बर्मा में अंततः लोकतंत्र आएगा और वहां के लोग तानाशाहों के चंगुल से निकलेंगे, तब वे मित्र देश भारत से पूछेंगे कि अपने स्वार्थ के लिए सिद्धांतों की बलि देकर नई दिल्ली को आखिर क्या मिला। दो दिन बाद हम आजादी का जश्न मनाएंगे। अभी भी मौका है, हम बर्मा के लोगों की आजादी की लड़ाई में उनके साथ खड़े हों, न कि उन शोषकों के साथ जिनका दिल चक्रवात नर्गिस में पिसे 14,000 अपनों के लिए नहीं पसीजा।

छोटी-सी बात

नफरत के खिलाफ संगीत

ऑस्ट्रेलिया में भारतीय छात्रों को निशाना बना रही नस्लवादी हिंसा का इससे बेहतर जवाब दूसरा नहीं हो सकता। ऑस्कर विजेता संगीतकार एआर रहमान ने आगामी जनवरी में सिडनी में निशुल्क म्यूजिक कंसर्ट का कार्यक्रम बनाया है, इस उम्मीद से कि यह दोनों समुदायों के बीच प्रेम और सौहार्द के पुल का निर्माण करेगा। जिस देश में किंवदंतियां प्रचलित हैं कि संगीत की शक्ति से दीये प्रज्ज्वलित हो जाते थे और बादल झूमकर बरसने लगते थे, आज उसी देश का एक यशस्वी संगीतकार नफरत के खिलाफ संगीत की ताकत को आजमाना चाहता है, इससे विश्व भर में भारतीय संस्कृति का मान बढ़ेगा।

डॉन से

संघर्ष की शुरुआत का संकेत

मुशर्रफ के खिलाफ एफआईआर के बाद आपातकाल के फैसले में शामिल अन्य लोगों पर गिर सकती है गाज।

करीब दो साल पहले लगाए गए आपातकाल के दौरान सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अवैध रूप से नजरबंद करने के आरोप में एक सेशन कोर्ट के निर्देश के बाद इस्लामाबाद पुलिस ने पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। यह एफआईआर पूर्व तानाशाह के खिलाफ आपराधिक अभियोग चलाए जाने की दिशा में पहला कदम हो सकती है। यह वक्त ही बताएगा कि वाकई में मुशर्रफ के खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा अथवा नहीं, लेकिन इसे कम से कम उनके आलोचकों और आपातकाल के समर्थकों के बीच भिड़ंत शुरू होने का शुरुआती खतरनाक संकेत तो माना ही जा सकता है। आपातकाल के आदेश पर भले ही मुशर्रफ ने दस्तखत किए हों, लेकिन आपातकाल की घोषणा के मसौदे में साफ कहा गया है कि उन्होंने (मुशर्रफ) यह कदम प्रधानमंत्री, चारों प्रांतों के गवर्नरों और सेना प्रमुख व अन्य वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों की बैठक में स्थिति की समीक्षा करने के बाद ही उठाया। इसका मतलब यही है कि मुशर्रफ के खिलाफ मुकदमा चलाने से उन सभी के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू करने का द्वार खुल जाएगा जिन्होंने उस बैठक में आपातकाल के प्रस्ताव का समर्थन किया था। इसलिए कोई भी कदम उठाने से पहले प्रशासन को मौजूदा लोकतांत्रिक ढांचे पर पड़ने वाले प्रभाव को ध्यान में जरूर रखना चाहिए।

FOUNDED BY QUAID-I-AZAM MOHAMMAD ALI JINNAH
DAWN

'डॉन' पाकिस्तान का प्रमुख अंग्रेजी अखबार है।

वक्रदृष्टि

सरकार फ्लू को रोकने के लिए हरसंभव कदम उठा रही है।

आज खास
इतिहास का पन्ना
स्टेनलेस स्टील

संयोग से हुई थी जंगरहित लोहे की खोज

आज के दिन हैरी ने खोजा था।

आज घर-घर में आमतौर पर इस्तेमाल में आने वाले स्टेनलेस स्टील की खोज का इतिहास बहुत ज्यादा पुराना नहीं है। इसकी खोज का श्रेय इंग्लैंड के हैरी बर्ले को दिया जाता है, जिन्होंने आज से ठीक 97 साल पहले 12 अगस्त 1912 को ऐसे पदार्थ को खोज निकालने का दावा किया था जिस पर हवा-पानी का कोई असर नहीं हो सकता था। उस समय उसे जंगरहित स्टील का नाम दिया गया जो आगे चलकर स्टेनलेस स्टील कहलाया। इस स्टील में 10.5 फीसदी क्रोमियम था और आज इस्तेमाल होने वाले स्टील में क्रोमियम की इतनी ही मात्रा मिलाई जाती है। हालांकि इस खोज की घोषणा जनवरी 1915 में न्यूयॉर्क टाइम्स के एक आलेख में की गई थी। इसी साल हैरी बर्ले ने इसके पेटेंट के लिए आवेदन भी किया।

स्टेनलेस स्टील की खोज की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। हैरी बर्ले एक रसायन प्रयोगशाला में कार्य करते थे। विश्व युद्ध से पहले ब्रिटेन में हथियार उत्पादन में लगी कंपनियां बंदूकों की नलियों की भीतरी सतह जल्दी ही घिस जाने की वजह से बेहद परेशान थीं। इसका समाधान खोजने की जिम्मेदारी बर्ले को दी गई। उन्होंने पाया कि भीतरी सतह गोली से निकलने वाली गर्मी से घिस जाती थी। इसके लिए उन्होंने लोहे में क्रोमियम को मिलाकर ऐसा इस्पात बनाने का प्रयास किया, जिसका गलनांक बिंदु उच्च हो। लेकिन इस तरह के मिश्रण से जो इस्पात निकलकर आया, उसे जंग से भी रहित पाया गया और इस प्रकार स्टेनलेस स्टील की खोज हुई।

दरअसल स्टेनलेस स्टील की खोज के लिए प्रयास 19वीं सदी के पूर्वार्द्ध में ही शुरू हो चुके थे। वर्ष 1821 में एक फ्रांसीसी बर्थियर को क्रोमियम मिश्रित ऐसा इस्पात मिला, जिस पर कुछ अम्लों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। वर्ष 1872 में एक ब्रिटिश कंपनी वुड्स एंड क्लार्क ने ऐसे मिश्रित इस्पात के लिए पेटेंट हासिल करने का आवेदन किया था, जो एसिड और वातावरण की नमी का प्रतिरोधी था। इस मिश्रित इस्पात में 30 से 35 फीसदी क्रोमियम और दो फीसदी तक टंगस्टन मिलाया गया था।

पाठकों के पत्र

भाजपा का मंथन

राकेश कठनेरा भोपाल

भारतीय जनता पार्टी शिमला में एक विचार मंथन शिविर का आयोजन कर रही है जिसमें यह विचार किया जाएगा कि हम क्यों हारे। बड़े अफसोस कि बात है कि राष्ट्र की समस्याओं पर विचार करने के बजाय इस पर विचार किया जा रहा है कि हमारी पराजय के क्या कारण रहे। कितना अच्छा होता यदि यह विचार करते कि मुंबई में आतंकी हमला होने और स्पष्ट प्रमाण होने के बावजूद क्यों हम कुछ नहीं कर पाए। खाद्यान्न क्यों महंगे होते जा रहे हैं। महंगाई की जड़ में क्या है? यदि ऐसी समस्याओं पर मंथन होता तो ज्यादा अच्छा होता।

हड़ताल से नुकसान

राजा सिंह गुना

देश में आंदोलनों और हड़तालों की बाढ़ आई है उससे जन मानस को बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। साथ ही देश को करोड़ों की संपत्ति का नुकसान होता है। आम लोग अपनी जान तक इन आंदोलनों में गंवा देते हैं। जिस तरह जूडा की हड़ताल के दौरान हुआ। इस सबका जिम्मेदार कौन? इस पर विचार करना होगा। क्या हो सकता है इसका निदान, इस बारे में समाज और सरकार को मिलकर गंभीरता से विचार करना होगा और इसका कोई शांति पूर्ण हल निकालना होगा।

आज का इतिहास

1784 ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय प्रशासन के लिए पिट्स इंडिया विधेयक पारित।

1926 क्यूबा के क्रांतिकारी नेता और पूर्व राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रो का जन्म।

1940 द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन के साथ युद्ध प्रारंभ।

1946 अंग्रेजी के विश्वप्रसिद्ध लेखक एचजी वेल्स का निधन।

1956 लोकसभा द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग विधेयक पारित।

1960 सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक ने खुद को फ्रांस से आजाद घोषित किया।

2008 माइकल फेल्प्स ने सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक लेकर विश्व कीर्तिमान स्थापित किया।